राष्ट्रनिर्माण का यह एक अजीब नुस्खा है , सुखराम और मुकुल रॉय का भाजपा में शामिल होना

याद कीजिये संसद कितने दिन बाधित की गयी थी सुखराम के लिये । मुकुल रॉय के बारे में कितने ट्वीट और बयानबाज़ी की गयी थी । पर आज वही दोनों दागी कमल पत्र पर हैं ।

- ओम थानवी -

चोला और पाला बदलकर अभी - अभी बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय और देश को उनकी 'फौरी जरुरत' समझने के लिए गूगल की गलियों में डाउन द मेमोरी लेन की सैर कर कर रहा था। एक बार आप लोग भी गूगल के गलियारों में घूम आइए. 'की वर्ड' मैं ही दे देता हूं, ताकि आपको ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। 'मुकुल रॉय और भ्रष्टाचार', 'मुकुल रॉय शारदा', 'मुकुल रॉय नारदा', 'मुकुल रॉय सीबीआई', 'मुकुल रॉय गिरफ्तारी', 'मुकुल रॉय घोटाला', 'मुकुल रॉय स्टिंग' समेत मुकुल रॉय के साथ इन विशेषणों के बाकी पर्यायवाची शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए गूगल सर्च करें। मुकुल रॉय साहब की काली कथा का हिसाब - किताब वाले सैकड़ों पन्ने खुलते जाएंगें। उन्होंने हाल के वर्षों में बंगाल की सिसायत में किन वजहों से नाम कमाया है, उसकी तफसील से जानकारी भी मिल जाएगी। अगर आपको हिन्दी सर्च में दिक्कत हो तो अंग्रेजी में इन्ही शब्दों का तर्जुमा करके सर्चे करें। नतीजे और ज्यादा विस्तार से मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। उसके बाद आप एक और 'की वर्ड 'सर्च करें - 'मुकुल रॉय बीजेपी '। इस सर्च से आप ये समझ पाएंगे कि बीजेपी और मुकुल रॉय के बीच बीते कुछ दिनों से कैसी खिचड़ी पक रही थी ? साझा चूल्हे पर कब से और कितनी आंच में खदक रही थी ? साथ ही बीजेपी नेताओं ने अपने मुखारविंद से बीते महीनों -सालों में मुकुल रॉय साहब को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए जिन शब्दों और बयानों से नावाज गया है, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। मुकुल रॉय बंगाल की राजनीति के वो वीर हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई नाम तोते के पास सबूतों का पुलिंदा है। शारदा घोटाले में मुकुल रॉय का नाम आया था। नारादा स्टिंग में उनके घोटालों का सबूत आया था। संक्षिप्त में सिर्फ इतना बता दें कि सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 13 लोगों के खिलाफ अप्रैल में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें सांसद मुकुल रॉय का भी नाम है। 11 सितंबर को केंद्र की दो एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नारदा स्टिंग जांच के सिलसिले में मुकुल रॉय से पूछताछ की थी. यानि उनकी गर्दन सीबीआई के शिकंजे में थी। अभी भी होगी शायद लेकिन एक फर्क अब आ गया है। उनके कंधे पर देश की सत्ताधारी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हाथ आ गया है। गर्दन सीबीआई के हाथ में रहे तो रहे।

जब से शारदा -नारदा का मामला उजागर हुआ है तब से जितने भी बीजेपी नेता बंगाल गए हैं, सब ममता और उनके सिपहसालार मुकुल रॉय के सिर पर घपलों -घोटालों का घड़ा फोड़कर ही वापस आए हैं। बीजेपी के बंगाल प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तो मुकुल रॉय के बारे में बयानों का रिकार्ड बना चुके हैं। दिल्ली से चलने वाली बीजेपी के आईटी सेल से भी मुकुल रॉय के घोटालों को पब्लिक डोमेन में विस्तार देने के लिए न जाने ट्वीट, रिट्वीट कराए जाते रहे हैं। मुकुल रॉय के चेहरे पर भ्रष्टाचार की कालिख पुती रहे और इस कालिख के बड़े हिस्से का छिड़काव ममता बैनर्जी पर होती रहे, ये काम सोशल मीडिया पर गोले दागने वाले बीजेपी के सायबर वीर करते रहे हैं। गूगल सर्च से आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे सीबीआई ने मुकुल रॉय को घोटालों के आरोप में दबोचा ? कैसे अपने प्यारे मुकुल रॉय को सीबीआई के शिकंजे से बचाने के लिए ममता बैनर्जी सीधे पीएम मोदी पर लगातार मिसाइल दाग रही थीं ? सड़क पर उतरने को तैयार थीं। बयान दे रही थीं कि उनके मुकुल रॉय को पीएम मोदी के इशारे पर फंसाया जा रहा है। तभी खबर ये फैली कि मुकुल रॉय खुद बचने के चक्कर में घर का भेदी बनने को तैयार हो गए हैं। ममता और अपनी पार्टी के गोरखधंदे की जानकारियां लीक करके मदद सीक कर रहे हैं।

कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि रॉय साहब सीबीआई के दवाब में आ गए थे. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए टीएमसी से जुड़ी जानकारी एजेंसी को दी थीं. इसी बीच बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से उन्हें ऑफर मिलने की खबरें भी अंतःपुर में आने लगी थी। ममता ने उन्हें पार्टी से बाहर रास्ता दिखाने का फैसला किया तो मुकुल राय साहब ने भी कहा -तुम क्या निकालोगे, मैं ही नहीं रहूंगा पार्टी में। उसके बाद जो हुआ, वो सामने है। उधर से इधर आ गए। अब कह रहे हैं कि ममता राज को उखाड़ने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। सीबीआई उन्हें 'ममतापुर' से उखाड़कर फिर से सलाखों के पीछे भेजती, उससे पहले ही नए राष्ट्र के निर्माण यक्ष में आहूति देने के लिए बुला लिया गया है।

कालेधन के खिलाफ नोटबंदी वाली क्राति की पहली वर्षगांठ से ठीक पांच दिन पहले बंगाल का ये प्रतापी नेता को पवित्रतावादी पार्टी का एक अहम किरदार बन गया है। अब उनके पाप धोने के लिए आने वाले दिनों में बीजेपी प्रवक्ता को नई दलीलें देते हुए सुनेंगे। मुकुल रॉय की हाईकमान रहीं ममता बैनर्जी को भ्रष्टाचारी और मुकुल रॉय को सदाचारी साबित करने तर्क गढ़े जाएंगे। वैसे ही जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ डूबे हिमाचली नेता पंडित सुखराम को अपने गंगा जल से आचवन कराने के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तीन दिन पहले कहा - जो बीत गई, सो बात गई। कानून अपना काम करेगा । हरिवंश राय बच्चन ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इस कविता का इस्तेमाल कोई सत्ताधारी दल सुखराम जैसों का पाप धोने के लिए करेगा। सुखराम के मामले में बीजेपी नेता का ये तर्क सुनकर तो ये लगा था कि बीजेपी अब खुले तौर पर 'जो बीत गई सो बात गई वाली कैटेगरी 'के भ्रष्टाचारी नेताओं को धो-पोछकर जरुरत के हिसाब से अपने शोकेस में सजाने को तैयार है। सुखराम का मामला तो वैसे भी करीब बीस साल पुराना है। तो बीजेपी ने हो सकता है कि कोई मियाद तय कर ली होगी कि भ्रष्टाचार का मामला अगर पुराना हो। मौसम अगर चुनावी हो। नेता अगर वोटजुटाऊ हो तो 'जो बीत गई सो बात गई ' कहकर उसे अपने घाट का पानी पीने के लिए बुलाया जा सकता है। भ्रष्टाचारी अगर वोटबैंक वाला हो तो उसके अतीत पर गंगाजल से पोछा मारकर अपने पाले मे लिया जा सकता है। मुकुल रॉय के स्वागत सत्कार के बाद तो लगता है कि जो बीत गई सो बात गई कि मियाद महीने -दो महीने तक भी हो सकती है। पाप करो उधर, साफ करो इधर की तर्ज पर ज्चुनाव जीतने के लिए साम-दाम-दंड-भेद को अपनाने की मिसाल है मुकुल रॉय जैसे नगीनों को पार्टी में इंट्री। ऐसी इंट्री पहले भी होती रही है। आने वाले दिनों में इंट्री के दरवाजे को और चौड़ा किया जा सकता है। ज्यादा आओ। ज्यादा लाओ (वोट)।

अब मेरा एक सुझाव है। बीजेपी को 'जो बीत गई सो बात गई 'वाली राष्ट्रीय लिस्ट बनानी चाहिए। बीतने की एक मियाद तय कर दें। ऐलान कर दें कि गुनाह किस -किस दर्जे का और कितने दिनों पुराना होगा तो उसे बीतने की श्रेणी में जाल दिया जाएगा। पार्टी को अपने नए विधान -संविधान में भी 'जो बीत गई सो बात गई' वाली कैटेगरी का जिक्र कर देना चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ। पार्टी में इंट्री के ख्वाहिशमंदों को भी पता रहेगा कि वो कब इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर पार्टी ने न कोई सवाल पूछा जाएगा। न नेताओं को बचाव में नई कविता सुनानी पड़ेगी। फायदा ये होगा कि हर राज्य से बीजेपी को ऐसे प्रतापी जेल रिटर्न नेता मिल जाएँगे, जो चुनावी मौसम में शिद्दत से पार्टी की तूरही बजाएँगे। ऐसे खेले -खाए -पीए -अघाए नेताओं को 'जो बीत गई सो बात गई ' के नारे के साथ पार्टी में शामिल करने के कई फ़ायदे भी होंगे। मालदार आसामी के अंदर आने से पार्टी पर कम से उनके इलाक़े के खर्चे का लोड नहीं पड़ेगा। ठीक -ठाक वोट पड़ेगा,सो अलग। हर्रे लगे न फिटकिरी रंग चोखा आए। लोकसभा चुनाव में भी अब डेढ़ साल ही रह गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे वीतरागी नेताओं की जनगणना का काम शुरु कर देना चाहिए। पहली और बड़ी खेप तो यूपी -बिहार से ही पार्टी को मिल जाएगी। जिनके अतीत पर गंगा जल से पोछा मारकर 'जो बीत गई सो बात गई ' नारे के साथ कमल निशान के साथ मैदान में उतारा जा सकेगा। पब्लिक मेमेरी भी छोटी होती है। जनता अपने जनार्दन के गुनाह जल्दी भूल जाती है। कई बार जनता गुनाह वाले को ही अपना जनार्दन मानकर जिता देती है। जब जनता अपना स्टैंड चेंज कर सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं ? जिस भी पार्टी को ऐसे लोगों की दरकार हो, उनका गुनाह भूलकर उन्हें नए सिरे से कबूल करें।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 2017 नवम्बर के अंक में राष्ट्रीय, प्रांतीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। दिल्ली पलवल के बीच शटल में असावटी के पास संघ परिवार से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा 15 वर्षीय जुनैद की हत्या के बाद उपजे जन आक्रोश व राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार की आलोचना होने पर पुलिस ने संघ समर्थक हत्यारों की गिरफ़्तारी तो की थी परन्तु जब अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चला तो हरियाणा सरकार के एडिशिनल एडवोकेट जनरल के माध्यम से संघ परिवार से समर्थित हत्यारों को अदालत में बचाने का प्रयास किया गया, जिसका लेख 'जुनैद हत्या कांड: न्याय की राह में संघ के झटके, जज ने किया एतराज' में वर्णन किया गया है। पुलिस द्वारा की जा रही जांच से असंतुष्ट होकर जुनैद के पिता ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में हल्फनामा देकर पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किये तो पुलिस ने हल्फनामे में जुनैद के पिता पर आरोपियों के साथ समझौते के लिये दो करोड़ रुपए और तीन एकड़ ज़मीन की मांग की सौदेबाजी करने का आरोप लगाया जिसे जुनैद के पिता ने इन्कार कर दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस की जांच से असंतुष्ट पीड़ित परिवार द्वारा सीबीआई से जांच की मांग करने वाली दायर याचिका के मामले में सीबीआई ने भी अपना जवाब दाखिल करते हुए दलील दी कि उसके पास स्टाफ़ की कमी व काम का बोझ काफ़ी ज्यादा है, इसलिये इस मामले की जांच पुलिस से ही करवाई जाय। इस मामले में पुलिस की जांच पहले ही सवालिया घेरे में है।

'मामा की दिवाली सवा करोड़ की- क्राइम कंट्रोल कैसे हो जब थाने-चौकियों नेताओं की सेवा में हो' व 'एस एचओ को भारी पड़ा कमिश्नर को दिवाली रिश्वत पहुंचाना' लेखों द्वारा पुलिस तथा नेताओं के बीच लूट के मामले में गठजोड़ का पूरा भंडा-फोड़ किया गया है। पुलिस के छोटे से सिपाही से लेकर उच्चतम अधिकारी आईपीएस डीजीपी को भी अपने पदों पर बने रहने के लिये नेताओं व सरकार के निर्देशों की पालना करनी पड़ती है। इसी कारण दोषियों को अपराध करने व लूट करने की खुली छूट रहती है जबकि निर्दोष को झूठे मुकदमे में फसाया जाता है। इसलिये जनता में पुलिस की छवि धुमिल हो रही है और लोग पुलिस के खिलाफ़ भी हाथ उठाने में नहीं हिचकते, जिस कारण कई बार पुलिस वाले पिट भी जाते हैं जिसका लेख 'दिवाली की रात पिटा थानेदार आखिर क्यों ?' द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है।

भाजपा की मोदी सरकार टेलीविजन व सोशल मीडिया पर तथा भाषणों में भ्रष्टाचार मिटाने व भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने पर लम्बे-चौड़े भाषण दे रही है, परंतु व्यवहार में सरकार भ्रष्टाचारियों को दंडित करने की बजाए उनको बचाने के लिये कानून बना रही है जो सरकार द्वारा करोडों मतदाताओं को दिये आश्वासन तथा मतदाताओं द्वारा सरकार को दिये गये अधिकार का उल्लंघन है। महाराष्ट्र व राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर न्यायाधीशों, मैजिस्ट्रेटों, विधायकों व लोकसेवकों की सुरक्षा के नाम पर उनको अपराध करने की खुली छ़ट दे रही है, जिसका लेख 'उखाड़ फेंकेगी जनता' में संवैधानिक परिपेक्ष्य में विवेचन किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ़ वहां का पूरा मीडिया खड़ा हो गया है तो भारत में भाजपा, संघ परिवार व प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ़ लिखने व बोलने वाले पत्रकारों व साधारण नागरिकों की गिरफ़्तारियां हो रही हैं, काला कानून लाया जा रहा है, फ़िल्मों से सीन हटाए जा रहे हैं तथा राजनैतिक दलों के खिलाफ़ झूठे मामले गढे जा रहे हैं। इनसे सम्बन्धित घटित घटनाओं का लेख ''बेमिसाल भाजपाई तानाशाही: पत्रकार व दुकानदार की गिरफ़्तारी, 'मर्सल' पर कैंची व राजस्थान का काला कानून' में तथ्यात्मक वर्णन किया गया है। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी व उसकी सरकार तथा संघ परिवार की आलोचना करता है अथवा असहमति प्रकट करता है उसे राष्ट्रद्रोही की संज्ञा देने में देरी नहीं लगती। फिल्म 'पद्मावती' तथा निर्माता संजय भंसाली का राजपूत करणी सेना, विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारें, विश्व हिंदु परिषद तथा बजरंग दल द्वारा कट्टर विरोध किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ़ जनता अपने मौलिक अधिकारों व असहमति के अधिकार की रक्षा के लिये डटकर खड़ी हो जाए और अपनी आवाज़ बुलंद करें।

'अच्छे दिनों' के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के शासन काल में संगठित क्षेत्र के मज़दूरों की हालत बद्तर होने जा रही है। निवेश व रोजगार बढाने के नाम पर श्रम कानून में सुधार किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य उद्योगपतियों, नियोक्ताओं व कॉरपोरेट घरानों को बिना किसी जिम्मेदारी व जवाबदेही के आसानी से अनाप-शनाप कमाने के लिये रास्ता उपलब्ध कराना है, जिसका लेख 'श्रम कानूनों को बदलने की तैयारी ? यानी भारत में सुरक्षात्मक श्रम कानूनों की खात्में की शुरूआत' में सटीक विश्लेषण किया गया है। मज़दूरों के हकों पर इस तुगलकी का पूरा देश में किए जा रहे विरोध को और ताकतवर बनाने के लिये लोगों को इसका डटकर साथ देना चाहिये।

गौ-गुंडों द्वारा गौ रक्षा के नाम पर की जा रही हिंसा पर 'नागा बाबा नहीं हूं, वो अभी-अभी मेरी गौरच्छा करके गए हैं साब', बीफ़ के नाम पर की जा रही हिंसा व प्रतिरोध पर 'मेघालय में बीफ़ बैन नहीं करेंगे: बीजेपी', संघ परिवार व भाजपा के अनेक मंत्रियों द्वारा ताजमहल की एतिहासिकता पर किए जा रहे विवाद पर ताज ' 2019' तथा भाजपा सरकार द्वारा विकास, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत व बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने पर '' 'विकास' ताक रहा है, 'स्वच्छ भारत', हाथ में बोतल लेकर 'डिजिटल भारत' के साथ, इंतजार कर रहा है 'बुलेट ट्रेन' के आने पर'' कार्टून द्वारा मोदी सरकार की नीतियों पर उचित व्यंग्य किया गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी महत्वपूर्ण व प्रशंसनीय हैं।

-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता